viuh ckr

तिब्बत में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध गलत

चीन की उपनिवेशवादी सरकार ने तिब्बत में मोबाइल इंटरनेट के उपयोग पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर तिब्बतियों के मौलिक अधिकार का हनन किया है। चीन सरकार का असल इरादा तिब्बत में सूचना के प्रवाह को और ज्यादा नियंत्रित करना है। उसके नए कदम से तिब्बत के बाहर वही जानकारी जा पाएगी, जिसे चीन की सरकार चाहेगी। यह पहले से ही जारी कठोर सेंसरशिप को और भी अधिक कठोर बनाने का जनतंत्रविरोधी प्रयास है।

विश्व स्तर पर ग्लोबल विलेज की बात हो रही है। नवीनतम वैज्ञानिक तकनीक, उपकरण तथा अनुसंधान पूरे संसार को ही एक समुदाय बनाने में लगे हैं। इसे कहते हैं ''वसुधैव कुटुंबकम्'' अर्थात् पृथ्वी एक परिवार । ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे बदलाव तथा शोध से सभी देश लाभ उठाने लगे हैं। इस प्रकिया को ज्यादा तीव्र एवं प्रभावी करने हेतु विश्वस्तर पर प्रयास निरंतर जारी हैं। सूचना–प्रवाह के क्षेत्र में भूमंडलीकरण की दृष्टि से लगाकर रचनात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे दौर में मोबाइल इंटरनेट पर तिब्बत में अनावश्यक प्रतिबंध ने चीन सरकार को सबके सामने बेनकाब कर दिया हैं।

तिब्बत पर अपने अवैध नियंत्रण के समय से ही चीन की सरकार दमन एवं अत्याचार की नीति पर चल रही है। चीनी दमन से तंग आकर आए दिन तिब्बत में आत्मदाह की दुःखद धटनायें हो रही हैं। शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणी और लामागण भी स्वयं को आग के हवाले कर रहे हैं। शरीर में मामूली चोट लगने पर भी हमें काफी कष्ट होता है। लेकिन तिब्बत में तो लोग अपनी ही देह में आग लगाकर चीन सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विश्व समुदाय का ध्यान खींचने को मजबूर हैं। उनकी मांग है कि चीन द्वारा किया जा रहा अत्याचार बंद हो, तिब्बत को आजाद किया जाए तथा परमपावन दलाई लामा जी को ससम्मान तिब्बत वापस लाया जाए । अपनी इसी उचित मांग को लेकर पिछले कुछ महीनों में ही लगभग सवा सौ तिब्बती आत्मदाह के जरिए देश के लिए आत्मबलिदान कर चुके हैं। आत्मदाह की धटनायें विचलित करने वाली हैं। लेकिन चीन की सरकार तिब्बत संबंधी अपनी दमनात्मक नीतियों में बदलाव लाने की जगह उन्हें और भी क्रूर तथा हिंसक बनाने में लगी है। मोबाइल इंटरनेट को प्रतिबंधित करने का प्रयास इसी तरह का एक धिनौना प्रयास है। चीन की सरकार चाहती है कि तिब्बत के बारे में विश्व को उन्हीं बनावटी बातों का पता चले जिन्हें वह बताना चाहती है।

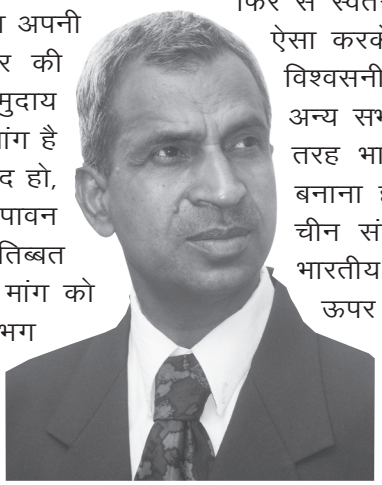

तिब्बत की दयनीय स्थिति के संबंध में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन सी पी), अरुणाचल प्रदेश ने भारत सरकार के नाम अपील जारी करके बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। उसने भारत सरकार से अपनी चीन–नीति में बदलाव की मांग की है। उसका मत है कि तिब्बत के हितों की उपेक्षा करके भारत के साथ चीन के संबंध मजबूत नहीं हो सकते । तिब्बत हमेश से भारत और चीन के बीच बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) रहा है। इसीलिए प्राचीनकाल से भारत और चीन के संबंध अत्यंत मधुर रहे थे। दुर्भाग्यवर्ष तिब्बत पर चीन के अवैध नियंत्रण के साथ ही चीन की सरकार भारत को चौतरफा अपमानित करने तथा नीचा दिखाने और भारतीय भूभाग पर गैरकानूनी ढंग से कब्जा करने की नीति पर चल रही है। इसी के परिणामस्वरुप 1962 के बाद भी चीन की सरकार भारत के नए –नए क्षेत्रों पर अपने दावे जताती आ रही है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह 14 नवम्बर 1962 के सर्वसम्मत संसदीय प्रस्ताव के अनुरुप चीन के अवैध कब्जे से विशाल भारतीय भूभाग को मुक्त कराने का प्रयास करे। तिब्बत को चीन के चंगुल से आजाद कराकर उसे फिर से स्वतंत्र मध्यस्थ राज्य बनाने हेतु कदम उठाए । ऐसा करके ही चीन के साथ अपने संबंधों को भारत विश्वसनीय और मजबूत बना सकता है। भारत के अन्य सभी राजनीतिक दलों को भी एन सी पी की तरह भारत सरकार पर उचित एवं पर्याप्त दबाव बनाना होगा । सभी राजनीतिक दल तिब्बत तथा चीन संबंधी अपनी नीतियों को सामने लायें और भारतीय जनता एवं भारत सरकार के मनोबल को ऊपर उठायें। ◆

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)
E-mail :- shyamnathji@gmail.com

आत्मदाह की 119वीं घटना में वांगछेन डोलमा का निधन

¼Qk;y] 17 tu] 2013½

तिब्बत पर लगातार चीनी कब्जे के विरोध में पूर्वी तिब्बत के खम प्रांत स्थित ताउ क्षेत्र में गत 11 जून को खुद को आग लगा लेने वाली भिक्षुणी वांगछेन डोलमा काफी मात्रा में जल जाने की वजह से दम तोड़ दिया है।

इसके बाद से ही उनके परिवार के सदस्यों को चीनी प्रशासन ने नजरबंद रखा है और उस इलाके में संचार के सारे साधनों पर रोक लगा दी गई है।

धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन के अनुसार गत 14 जून को डार्टसेडो के एक अस्पताल में वांगछेन डोलमा का निधन हो गया जहां चीनी सुरक्षा बल विरोध प्रदर्शन स्थल से उन्हें जबरन उठाकर ले गए थे। इसके बाद प्रशासन के लोगों ने डोलमा के परिवार वालों को बताए बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जैसा कि अन्य आत्मदाह करने वालों के साथ किया जाता रहा है।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने कहा, "प्रशासन ने चुपके से अस्पताल में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने मृतक के परिवार वालों को भी घर में नजरबंद करके रखा हुआ है।"

ऐसी खबर है कि परिवार वालों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद स्थानीय तिब्बती उनके घर के पास श्रद्धांजलि देने के लिए जुट रहे हैं। वांगछेन डोलमा ने गत 11 जून को सायं करीब 5 बजे ताउ के न्यात्सो मठ के बाहर खुद को आग लगा लिया जहां समूचे तिब्बत से आए हजारों भिक्षु एक बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए जुटे थे।

बताया जाता है कि आत्मदाह से एक दिन पहले 10 जून की शाम को वांगछेन डोलमा ताउ के एक स्कूल में विद्यार्थियों को सलाह दिया कि वे मेहनत से तिब्बती भाषा की पढ़ाई करें।

वांगछेन डोलमा का जन्म ताउ के मिनयाग ड्रापा इलाके में हुआ था। उनके गांव के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी भरशाब ड्रगकार के एक बौद्ध संस्थान में उनका दाखिला कराया गया था।

इसके पहले आई खबरों से यह पता चला है चीनी सुरक्षा कर्मियों ने एक अज्ञात तिब्बती व्यक्ति की जमकर पिटाई की है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। यह व्यक्ति चीनी प्रशासन को वांगछेन डोलमा को अपने कब्जे में लेने से रोक रहा था। यह पता नहीं चल पा रहा है कि वह व्यक्ति कहां है और उसकी हालत कैसी है।

वर्ष 2009 से अब तक चीनी शासन के तहत रहनेवाले 119 तिब्बतियों ने स्वाधीनता और परमपावन दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाने की मांग के साथ आत्मदाह किया है। इनमें से 102 लोगों की मौत हो गई है और बाकी लोगों की दशा के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। ◆

एनसीपी ने केंद्र सरकार, अरुणाचल सरकार से चीन नीति की समीक्षा करने को कहा

¼VkbEl vkQ bfM;k] bVkuxj] 17 tu½

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की अरुणाचल प्रदेश ईकाई ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से अनुरोध किया है कि वे चीन के प्रति अपनी नीति की समीक्षा करें और तिब्बत आंदोलन का समर्थन करें।

चीनी प्रशासन द्वारा तिब्बतियों के बुनियादी मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे–खासकर संस्कृति और धर्म के मामले में, आर्थिक साम्राज्यवाद के द्वारा तिब्बतियों को आक्रामक तरीके से हाशिए पर धकेलना और उसके विशाल जल व खनिज संसाधनों के दोहन पर चिंता जताते हुए पार्टी ने राजनेताओं से यह अनुरोध किया है कि वे तिब्बती समस्या की गंभीरता को समझें और चीन के प्रति भारत के रवैए में जल्दी ही बदलाव की शुरूआत करें।

पार्टी के राज्य अध्यक्ष कहफा बेंगिया ने रविवार को कहा, "तिब्बत के विभिन्न इलाकों में आत्मदाह की अनगिनत घटनाएं और पूरी दुनिया के बौद्ध भिक्षुओं में बढ़ती अशांति अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय है और यह स्थिति की गंभीरता को बताता है। केंद्र सरकार की विदेश नीति के मामले में सबसे बड़ी गलती तिब्बत और उसकी समस्या को चीन का आंतरिक मामला मान लेना था। इस नरम, कायर और अस्पष्ट रवैए की वजह से ही 1962 में भारत को चीनी हमले का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि नीतियों में भारी बदलाव की शुरुआत करते हुए केंद्र सरकार को न केवल तिब्बत आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देना चाहिए, बल्कि देश में भी तिब्बती शरणार्थियों और तिब्बत के भीतर के लोगों के बारे में आवाज उठाने की अनुमति देनी चाहिए, खासकर अरुणाचल में जहां के लोग तिब्बत पर चीनी कब्जे से सबसे बुरी तरह से पीड़ित हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य में स्वतः स्फूर्त तरीके से तिब्बत समर्थक समूह (टीएसजी) का गठन किया गया है जिसमें आर.के. खिमे, अनोक वांगसा, कबाक टाचो और अन्य कई प्रमुख नेता शामिल हुए हैं। बेंगिया ने कहा कि इसमें राज्य के कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं जिन्होंने तिब्बत आंदोलन को बिना शर्त समर्थन दिया है और यह स्वागतयोग्य बात है। ◆

तिब्बत को कवर करने वाले फ्रांसीसी पत्रकार और टीवी चैनल को चीन सरकार द्वारा धमकी दिए जाने की आलोचना

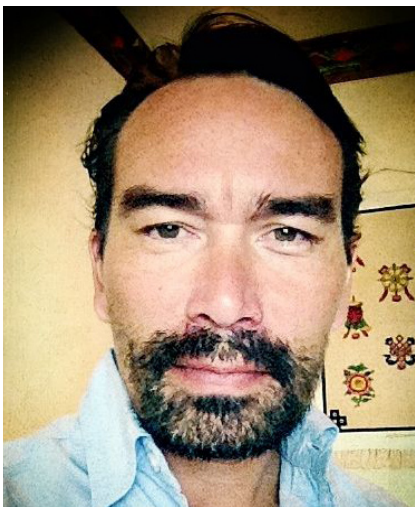

सिरिल पेयेन, फ्रांसीसी पत्रकार

¼frCcrujh0;। MkV uV] 13 tu] 2013½

मीडिया पर निगरानी रखने वाले पेरिस स्थित संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने 11 जून को इस बात पर भारी नाराजगी जाहिर की है कि चीनी राजनयिक ने एक फ्रांसीसी पत्रकार को लगातार गंभीर तरीके से प्रताड़ित किया है। इस पत्रकार ने मई के शुरुआत में गुप्त रूप से तिब्बत के सात दिन के दौरे पर जाकर अपने टीवी चैनल पर वहां के हालात की जानकारी दी थी। सिरिल पेयेन नाम के इस पत्रकार ने राजधानी ल्हासा का गुप्त रूप से फिल्मांकन किया था और तिब्बतियों के इंटरव्यू लिए थे। उनके मुताबिक यह शहर जॉर्ज ऑरवेल की रचनाओं की तरह गोपनीय निगरानी वाला इलाका है। उनके कार्यक्रम "सेवन डेज इन तिब्बत" का प्रसारण फ्रांसीसी समाचार चैनल फ्रांस 24 पर 30 मई को प्रसारित किया गया।

चीन द्वारा उनकी प्रताड़ना 3 जून को शुरू हुई, जब चीनी दूतावास से एक प्रतिनिधि ने पेरिस स्थित टीवी चैनल के मुख्यालय में जाकर पेयेन से मिलने की जिद की और कहा कि चैनल के वेबसाइट से इस डॉक्यूमेंट्री को हटाया जाए। लेकिन पेयेन चैनल ऑफिस में नहीं थे और वे थाइलैंड जा चुके थे। करीब दो घंटे की बहस–धमकी के बाद भी चैनल ने दूतावास की मांग को मानने से इनकार कर दिया।

थाइलैंड के शहर बैंकॉक में 4 जून को पेयेन के कदम रखते ही चीनी दूतावास के अधिकारियों ने पेयेन को उनके मोबाइल फोन पर धमकी दी और कहा कि वह तुरंत दूतावास आकर उनसे मिलें। पेयेने ने कहा कि किसी होटल में मिल लेते हैं, लेकिन उन्होंने इस सुझाव को नहीं माना। दूतावास के अधिकारियों ने इसके बाद उन्हें कई बार बिना परिचय दिए फोन किया और कई एसएमएस भेजे। दूतावास की एक महिला कर्मचारी के ऑडियो संदेश में कहा गया था कि पेयेन एक बार दूतावास आएं और इसकी सफाई दें कि आखिर क्यों उन्होंने चीनी वीसा हासिल करने के लिए धोखाधड़ी की, वह मुलाकात को टालना बंद करें या इस इनकार की "जिम्मेदारी लें"।

आरएफएस ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने पेयेन और फ्रांस 24 के साथ के प्रति जिस तरह का व्यवहार किया है वैसे व्यवहार की उम्मीद सिर्फ माफियाओं से की जा सकती है, वरिष्ठ राजनयिकों से नहीं। आरएफएस ने कहा, "यह बात स्वीकार्य है कि कोई दूतावास किसी समाचार रिपोर्ट पर अपना असंतोष जाहिर करे। लेकिन यह बात पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि फ्रांस और थाइलैंड में बैठ राजनयिक एक समाचार चैनल को अपने संपादकीय सामग्री में बदलाव के लिए धमकी दें, किसी पत्रकार से उग्र भाषा में बात करें और पूछताछ के इरादे से उसे अपने पास आने का फरमान जारी करें।"

संगठन ने कहा है, "इन राजनयिकों ने एक फ्रांसीसी पत्रकार को जिस तरह से टेलीफोन से धमकी दी है उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए।" संगठन ने फ्रांसीसी प्रशासन से मांग की है कि वे पेरिस में चीनी दूतावास के प्रतिनिधियों को बुलाएं और एक फ्रांसीसी पत्रकार के अस्वीकार्य प्रताड़ना के लिए विरोध जताएं। ◆

वैश्विक मानवाधिकार संगठनों ने चीन से आग्रह किया कि वह तिब्बत के दुःखद हालात को खत्म करे

¼frCcrujh0;। MkV uV] 03 tu] 2013½

दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने चीन से यह आग्रह किया है कि वह तिब्बत की मौजूदा आपात स्थिति से निपटे। तुर्की की राजधानी इंस्ताबुल में 22 से 27 मई को अपने त्रिवार्षिक कांग्रेस में उन्होंने यह बात कही। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स (एफआईडी) के 38वें कांग्रेस में दुनिया के 117 देशों के 178 गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि जुटे थे।

कांग्रेस ने चीनी शासन वाले तिब्बत पठार में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की, खासकर आत्मदाह के मामलों की और जनवरी 2010 से ही तिब्बत एवं चीनी प्रतिनिधियों के बीच किसी तरह का संवाद न रहने की और इसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें तिब्बत के बारे में उक्त आह्वान किया गया। अपने प्रस्ताव में कांग्रेस में शामिल प्रतिनिधियों ने दलाई लामा के खिलाफ अभियान तीव्र होने और तिब्बत में चीनी सैन्य निर्माण की निंदा की और उन नीतिगत सख्ती की भी आलोचना की जो तिब्बतियों के आत्मदाह जैसे विरोध प्रदर्शन का मूल कारण हैं।

प्रस्ताव में चीन के नए नेतृत्व से यह आह्वान किया गया है कि वे तिब्बती प्रतिनिधियों से फिर से वार्ता शुरू करें, तिब्बत में 'स्थिरता बनाए रखने' के रवैए पर पुनर्मूल्यांकन करें और सुरक्षा तंत्र के प्रभुत्व को सीमित करें। इसके अलावा वे बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों, राजनयिकों और पत्रकारों को प्रोत्साहित करें और वे सभी तिब्बती इलाकों तक उन्हें जाने की इजाजत दें।

वर्ष 2012 में एफआईडीएच ने वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत (आईसीटी) के साथ साझेदारी में एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की जिसका शीर्षक थाः "मानवाधिकार उल्लंघन और आत्मदाहः

निर्वासित तिब्बतियों द्वारा प्रमाण"।

इस्तांबुल कांग्रेस का थीम था: "मानवाधिकार के संदर्भ से राजनीतिक बदलाव"। इसमें शामिल प्रमुख वक्ताओं में तुर्की के प्रधानमत्री अब्दुल्ला गुल, उप प्रधानमंत्री बेसिर अताले, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अध्यक्ष सांग सैंग हुन, यूरोपीय संघ में मानवाधिकार के विशेष प्रतिनिधि लम्ब्रिनिडिस, ईरानियन नोबल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन ईबादी, खाद्य अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदक ओलिवियर डी श्कटर और संयुक्त राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता की विशेष प्रतिवेदक आस्मा जहांगीर शामिल थीं।

वर्ष 1922 में स्थापित एफआईडीएच फ्रांस का सबसे पुराना और बड़ा मानवाधिकार संगठन है। नवीनतम कांग्रेस में ईरान के वकील डॉ. अब्दुल करीम लाहिदजी को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने सुश्री सौहयर बेलहसीन की जगह ली है जिन्होंने छह साल तक संगठन की अध्यक्षता की। कांग्रेस ने नए इंटरनेशनल बोर्ड का चुनाव किया है। आईसीटी के ईयू नीति निदेशक विंसेट मेटेन भी इंस्ताबुल कांग्रेस में शामिल हुए। ◆

दलाई लामा ने न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया का दौरा किया

आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के टाउनहाल में 17 जून को युवा सम्मेलन में युवकों के एक समूह के सवालों का जवाब देते हुए परमपावन दलाई लामा। फोटोः रस्टी स्टीवार्ट

¼frCcru jh0;: MkV uV] 20 tu] 2013½

न्यूजीलैंड में दलाई लामा ने समूची मानवता के खुलेपन पर जोर दिया

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 10 जून से न्यूजीलैंड की चार दिवसीय यात्रा शुरू की। अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने एक धार्मिक उपदेश और क्राइस्ट चर्च में एक सार्वजनिक व्याख्यान से की जिसमें करीब 2,300 लोग जुटे थे। यह धार्मिक उपदेश चार श्रेष्ठ सच्चाइयों, सभी बौद्ध परंपराओं के आधार और बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश के बारे में था। उन्होंने अंतर–बौद्ध परिप्रेक्ष्य और अंतर–धार्मिक समायोजन, दोनों के लिहाज से बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या की।

दलाई लामा ने अपना सार्वजनिक व्याख्यान उसी जगह पर दिया जहां सैम जॉनसन को यंग न्यूजीलैंडर ऑफ दि ईयर 2012 से सम्मानित किया गया। हाल में क्राइस्ट चर्च में आए भूकंप में स्वयंसेवी कार्यों के समन्वय के लिए जॉनसन को यह सम्मान मिला। परमपावन ने इस बात पर जोर दिया कि हर कोई यह समझे कि समूची मानवता एक है और इस आधार पर अपना आचरण करे। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य निश्चित रूप से एक जैसे ही हैं और किसी को भी राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग, शिक्षा आदि के आधार पर इनमें मतभेद नहीं पैदा करना चाहिए। जब माइंडफूड मैगजीन के पत्रकार मारी मैकक्लस्की ने यह पूछा कि किसी व्यक्ति के प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता को क्या आध्यात्मिकता भोथरा करती है, तो दलाई लामा ने कहा कि जैसे कि हम भौतिक स्वच्छता की जरूरत को स्वीकार कर चुके हैं, उसी तरह हमारे अंदर भावनात्मक स्वच्छता की भावना भी होती है। उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत तरह की भावनाएं आती हैं, और जो लोग इसको बेहतर तरीके से समझते हैं वह बेहतर तरीके से इन पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

दलाई लामा ने आस्ट्रेलिया में वैश्विक आचार और शांति पर चर्चा की

दलाई लामा ने गत 18 जून को आस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के न्यू साउथ वेल्स इलाके में स्थित पार्लियामेंट हाउस में आचार पर एक चर्चा में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने मेलबर्न में जुटे करीब 5800 लोगों के सामने व्याख्यान दिया।

सिडनी पीस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दुनिया भर के लिए आचार पर इस चर्चा में 170 से ज्यादा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। एबीसी के पत्रकार एंड्रयू वेस्ट ने इस चर्चा की शुरुआत करते हुए दलाई लामा से यह पूछा कि तिब्बत में इन दिनों क्या हो रहा है, खासकर फरवरी 2009 से अब तक वहां हुए 119 आत्मदाह के संदर्भ में। दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत की स्थिति बहुत दुःखद है और पूरी तरह भय का माहौल है। उन्होंने का कि चीन में भी ऐसा ही है, एक वाकया याद करते हुए उन्होंने बताया कि 1990 के दशक में युवा चीनियों का एक समूह उनसे मिलने आया था और उन्होंने अपने देश को ऐसी जगह बताया था जहां कोई भी वास्तव में कुछ सोच या अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि वातावरण पूरी तरह भय और संदेह का है। उन्होंने उल्लेख किया कि चीन के पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ और जेल में बंद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता विद्वान लिउ जियाओबो, दोनों ने ही चीन में एक आज़ाद और ज्यादा खुले सोसाइटी की जरूरत के बारे में बोला था और यह भी कहा था कि यह अच्छा होगा कि जिन देशों में ऐसी आज़ादी है वे इसके लिए चीन का सहयोग करें।

मेलबर्न के कन्वेंशन सेंटर में "करुणा: अच्छाई की बुनियाद विषय पर आयोजित एक व्याख्यान में दलाई लामा ने इस बात पर जोर दिया कि समूची मानवता एक है, हर कोई खुशहाल जीवन की आकांक्षा रखता है और इसे हासिल करना उसका अधिकार है। उन्होंने कहा कि दूसरे के प्रति गर्मजोशी खुशहाल जीवन की चाबी है और हमें इसको बढ़ावा देने का रास्ता तलाशना होगा। उन्होंने कहा कि विकास और आंतरिक मूल्यों को प्रोत्साहित कर हम इस 21वीं सदी को करुणा और शांति की सदी मानते हैं। ◆

असहमति, मौत और राजनीतिज्ञों पर बात

आस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 13 जून को एबीसी टेलीविजन के 7.30 रिपोर्टर्स के लिए परमपावन दलाई लामा का इंटरव्यू लेते हुए ली सेलेस। फोटोः जेरेमी रसेल/ओएचएचडीएल

(एबीसी, १५ जून, २०१३)

frCcrh vk/;kfRed urk ijeikou nykbZ ykek l vkLVfy;kbZ ckMdk-fLVx dkikj'ku d bVj0; d v'k ;gk i'k gA nykbZ ykek 11 fnu d nkj ij vkLVfy;k vk, g, FkA

yh l;yl] iLrkrk% पिछले तीन साल में सौ से ज्यादा तिब्बतियों ने लगातार जारी चीनी शासन और बर्बरता के विरोध में खुद को आग लगा लिया है–जिसे कथित रूप से आत्मदाह कहा जाता है। यह उस देश के लिए एक परेशान करने वाला चलन है जो लंबे समय से चीन के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करता रहा है।

परमपावन, हमें समय देने के लिए धन्यवाद।

yh l;yl% D;k vki viu thoudky e frCcr vkj phu d chp ey&feyki dh dkbZ lHkkouk n[kr g\

nykbZ ykek% जी हां, निश्चित रूप से। उन्हें सच्चाई स्वीकार करना होगा। आप जानती हैं कि हमारी अलग संस्कृति, अलग भाषा है–इसलिए एक सार्थक स्वायत्तता के द्वारा इन विशिष्ट चीजों को बचाने का हमें पूरा अधिकार है और चीन के लोगों के साथ बने रहना हमारे लिए भी फायदेमंद है क्योंकि तिब्बत भौतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। चीन अब वास्तव में दुनिया की आर्थिक ताकत बन चुका है, इसलिए यह हमारे हित में भी है। आखिरकार आप देखिए कि किसी को अपनी प्रभुसत्ता के बारे में सोचने में ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखतीं। आप यूरा.
`पीय संघ का उदाहरण लें।

yh l;yl% phuh 'kklu vkj uhfr;k d fojk/k e Qjojh] 2009 d ckn l vc rd 100 l T;knk frCcfr;k u vkRenkg dj fy;k gA D;k bldk eryc ;g g fd frCcrh ykx vfgalk dk jkLrk NkM jg g\

nykbZ ykek% जी नहीं। मैं समझता हूं कि खुद को जलाना अपने आप में एक अहिंसा है। आप देखिए कि वे लोग चाहते तो आसानी से बम विस्फोट का सहारा ले सकते थे जिनमें ज्यादा लोगों की जानें जातीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने जीवन का बलिदान दिया। इसलिए यह भी अहिंसा का ही एक हिस्सा है।

yh l;yl% ;g n[kr g, fd bu elyk ij lcdk /;ku vkdf"kr dju d fygkt l vki fdru egRoi.k g] D;k vkidk bl ckr dh vk'kdk g fd phu ljdkj vkidh ekr dk brtkj dj jgh g rkfd og bl ey dk uLrukcn d fy, frCcr ij T;knk l[r dkjokbZ dj ld\

nykbZ ykek% कुछ सख्त रुख वाले लोग ऐसा सोचते होंगे। बहुत से ऐसे सख्त मिजाज लोग यह समझते हैं कि यदि दला. ई लामा नहीं रहते हैं तो कोई भी और, कोई भी तिब्बती साठ लाख तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

लh l;yl% rk vki ;g lkpr g fd frCcfr;k dk bl ckr d fy, vk'kfdr jguk pkfg, fd vkidh ekr d ckn D;k gkxk\

nykbZ ykek% निश्चित रूप से तिब्बतियों का उत्साह बरकरार रहेगा। दलाई लामा की संस्था 400 या 600 साल पुरानी है और बुद्ध धर्म, तिब्बत तो 2,000 साल पुराने हैं। इसलिए निकट भविष्य में आप देखेंगे कि दलाई लामा के बिना भी तिब्बत देश बचा रहेगा और तिब्बती भावना भी बची रहेगी।

yh l;yl % vki bl ckr dk fdl rjg l yr g fd vkLVfy;k dh i/kkue=h tfy;k fxykMZ u vkil feyu l budkj dj fn;k\

nykbZ ykek% कोई बात नहीं। मेरी चिंता आम लोगों से मिलने की है क्योंकि मेरी मुख्य प्रतिबद्धता, मुख्य रुचि मानवीय मूल्यों, मानवीय अनुराग, करुणा और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा देने की है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है। (हंसते हैं) यदि मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा होता और मैं प्रधानमंत्री से मिलना चाहता, वह मिलने से इनकार करतीं, तब मुझे निराशा होती, लेकिन मुझे तो उनसे कुछ नहीं पूछना है।

yh l;yl% vkiu igy dgk g fd phu dk vkfFkd iHkko c< jgk gA D;k vkid fy, ;g tkf[ke g fd phu tl&tl rkdroj gkrk tk jgk g] nfu;k Hkj d jktuhfrK vkil feyu l Mju yx g D;kfd o phu

dks ukjkt ugha djuk pkgrs\

nykbZ ykek% नहीं, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। मेरा मानना है कि असली बदलाव तिब्बत के भीतर से आएगा, बाहर से नहीं।

yh lsyl% D;k vkidks ekSr ls Mj yxrk g\

nykbZ ykek% मौत से डरना अनावश्यक है। मौत हमारे जीवन का हिस्सा है। (हंसते हैं) और बुद्ध धर्म में ऐसी आध्यात्मिक परंपरा है, जी हां परंपरा, कि हम एक के बाद दूसरे जीवन का वरण करते हैं। इसलिए मौत का मतलब कपड़े बदलने जैसा ही है। कपड़े जब पुराने पड़ जाते हैं तो हम उसे बदल लेते हैं। इसी तरह जब शरीर पुराना पड़ जाता है तो एक समय के बाद हम युवा शरीर को अपना लेते हैं।

yh lsyl% tc vki ihNs eqMdj vius thou dh rjQ ns[krs rks vki nykbZ viuh bPNk ls ugha cus Fks] ;g vufPNd gksrk gA D;k vkids eu esa dHkh ,slk [;ky vk;k fd ;fn vki nykbZ ykek ugha gksrs rks vkids fy, pht+sa dqN vkSj gksrhA

nykbZ ykek% यह सोचना अयथार्थवादी है। मैं इसे पसंद करूं या न करूं, मैं दलाई लामा हूं, इसलिए मेरे लिए यही बेहतर है कि उसके मुताबिक तय जिम्मेदारियों को निभाऊं और जीवन पद्धति को अपनाऊं। यह ज्यादा बेहतर है।

yh lsyl% D;k vkidks dHkh xqLlk] fujk'kk] fp<+ tSlh Hkkoukvksa dks nckuk iM+rk g\

nykbZ ykek% हूं...जब कुछ अधिकारी थोड़ी देर से आते हैं (तत्काल बात को अलग दिशा देते हुए) तो ऐसा होता है (हंसते हैं)। एक मनुष्य होने के नाते गुस्सा हमारे मस्तिष्क का हिस्सा है। लेकिन आप इसको काबू कर सकते हैं—गुस्सा जा सकता है। कभी भी अपने अंदर की कमियों को हावी होने दें जिससे फिर ढेर सारा संदेह, अविश्वास, नकारात्मक चीजें, ज्यादा चिंता पैदा हो।

yh lsyl% Bhd gS] ijeikou] cgqr&cgqr /kU;oknA

nykbZ ykek% धन्यवाद। ◆

एक मां जिसने तिब्बत के लिए खुद को जलाकर मौत को गले लगा लिया

आत्मदाह करने वाली कालक्यी अपने पति ट्रुइपे और तीन बच्चों के साथ (फाइल फोटो)

¼lqb&yh oh] jk;VlZ] ceklZ] phu] 6 twu½

मार्च माह में एक युवा तिब्बती महिला कालक्यी ने चीन के सिचुआन प्रांत के एक शहर बर्मा के एक मठ में बार–बार जाना शुरू किया। उसके करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक दुबली–पतली गुलाबी गालों वाली चार बच्चों की मां, यह महिला एक समर्पित तिब्बती बौद्ध थी। लेकिन इस वसंत में जामथांग जोनांग मठ की उसकी यात्रा कुछ अस्वाभाविक तरह की लग रही थी। कालक्यी ने दिन भर में कई बार आध्यात्मिक मंत्रोच्चार करने शुरू कर दिए थे, और वह दिन भर में कम से कम दो बार मठ में जाकर साष्टांग प्रणाम करने लगी।

मार्च 24 की एक तपते दोपहर को कालक्यी–जो बहुत से तिब्बतियों की तरह बस एक नाम से प्रसिद्ध थी–करीब 200 से 300 अन्य भक्तों की तरह मठ के गेट पर खड़ी थी। उसने अपने आपको मिट्टी के तेल से भिगो लिया और माचिस से आग लगा ली। वह तत्काल ही आग की लपटों से घिर गईं और चिल्ला–चिल्ला कर कुछ नारे लगाने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 15 मिनट के भीतर ही आग की लपटों में घिरी कालक्यी ने दम तोड़ दिया। वह अभी महज 30 वर्ष की थीं।

सिर्फ एक साल के भीतर किसी तिब्बती मां द्वारा आत्मदाह की यह नौवीं घटना है। राजनीतिक अवज्ञा के आत्मघाती आंदोलन से निकला यह भयावह और चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसके अंत होने के संकेत नहीं मिलते। वर्ष 2009 से अब तक तिब्बत और उसके आसपास के चीनी इलाकों में रहने वाले कम से कम 119 तिब्बतियों ने चीनी शासन के विरोध में आत्मदाह कर लिया है। इन घटनाओं में 102 की मौत हो चुकी है और ऐसी नवीनतम घटना 29 मई

को क्विंघई प्रांत में हुई। कालक्यी की मौत नाबा प्रशासनिक क्षेत्र में हुई आत्मदाह की 39वीं घटना थी। नाबा सिचुआन प्रांत के कोने में है। तिब्बती बहुल यह प्रशासनिक क्षेत्र वर्ष 2012 के बाद शुरू हुई आत्मदाह की लहर का भौगोलिक केंद्र बिंदु है। तिब्बती आत्मदाहों का अंतिम असर क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वर्ष 2010 में ट्यूनीशिया में एक फल बेचने वाले के आत्मदाह ने एक ऐसी क्रांति की चिंगारी सुलगा दी थी जिसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मीडिया पर चीन सरकार के प्रतिबंध की वजह से तिब्बत में बढ़ती आत्मदाहों की संख्या के बारे में चीन के भीतर या बाहर इस बारे में जानकारी बहुत सीमित ही हो पाती है।

फिर भी, कालक्यी की कहानी इस बात को रेखांकित करता है कि किस तरह से यह आंदोलन एक हताशाजनक नए चरण में आ चुका है, जिसमें आत्मदाह की घटनाएं बौद्ध भिक्षुओं से आगे निकलकर अब आम तिब्बतियों तक पहुंच चुकी हैं। अशांत तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र और चीन के अन्य तिब्बती हिस्सों में होने वाली मौतें खासकर दो व्यक्तियों के लिए चुनौती हैंः चीन के नए राष्ट्रपति शी जिनपिंग और निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा। कुछ तिब्बती विद्वानों ने दलाई लामा की इस बात के लिए आलोचना की है कि वे आत्मदाहों को बंद करने का आह्वान नहीं कर रहे हैं।

कालक्यी न तो कोई धार्मिक नेता थी, न ही वह चीनी शासन के खिलाफ असंतोष का स्रोत थी, न ही उसने कोई कानून तोड़े थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वह ऐसी महिला नहीं थीं जिनसे अधिकारियों को कोई समस्या हो।

उनके जीवन के बारे में पता करने पर इस बात का सुराग मिलता है कि आखिर उन्होंने क्यों अपने को आग लगा लिया। एक वजह हैः कुछ आम बौद्धों में उन भिक्षुओं के अनुकरण के लिए बढ़ता उत्साह जिन्होंने आत्मदाह की श्रृंखला शुरू की है।

रायटर्स के एक संवाददाता ने कालक्यी के आत्मदाह की पुष्टि की है और उसने सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू से पश्चिमोत्तर में करीब 550 किमी. दूर स्थित बर्मा की यात्रा कर उनके अंतिम दिनों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उनकी इस यात्रा से पहले और कोई भी विदेशी पत्रकार बर्मा नहीं गया था। कुछ तिब्बत विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी 2012 में उरगेन नाम के एक 20 वर्षीय स्टुडेंट की गोलीबारी में हुई मौत की घटना से ही शायद बर्मा इलाके में लोग आत्मदाह के लिए भड़के हैं। उरगेन तब मारा गया था, जब चीनी सुरक्षा बलों ने बर्मा में उन विरोध प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी जो एक युवक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तिब्बती मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इस युवक ने ऐसे पत्रक प्रकाशित किए थे जिसमें यह कहा गया था कि आत्मदाह स्वाधीन तिब्बत और परमपावन दलाई लामा की वापसी के समर्थन में हैं।

आत्मदाहों पर नजर रखने वाली तिब्बती लेखिका सेरिंग वुएजर इस गोलीबारी की घटना को एक महत्वपूर्ण बिंदु मानती हैं। इसके बाद से सिर्फ बर्मा में ही छह लोगों ने खुद मौत को गले लगा लिया है।

उन्होंने कहा, "तिब्बती इलाकों में बिल्कुल शांति नहीं है। हर स्थान विस्फोट के मुहाने पर है। एक बार चिंगारी लगी नहीं कि लोगों को गुस्सा विस्फोट में बदल सकता है।" बर्मा के अधिकारियों की इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई।

vkkr bykdk

तिब्बत में हिंसा 1950 से ही जारी है, जब बीजिंग ने इस इलाके को "अशांतिपूर्ण तरीके से मुक्त करने" का दावा किया था। बहुत से तिब्बतियों का कहना है कि चीनी शासन ने उनकी संस्कृति और धर्म को क्षरित कर दिया है। वे इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि दलाई लामा को भारत में निर्वासन से वापस लाया जाए और उनकी मातृभूमि को वास्तविक स्वायत्तता दी जाए। चीन सरकार लगातार तिब्बतियों के अधिकारों को कुचल रही है और यह शेखी बघार रही है कि वह उस इलाके में विकास और समृद्धि लेकर आई है।

वर्ष 2008 में, बीजिंग ओलंपिक खेल शुरू होने से कई महीनों पहले, तिब्बतियों को आज़ादी से वंचित रखने के विरोध में पूरे तिब्बत में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इसका बर्बरता से दमन किया गया। इसके तीन साल बाद वर्ष 2011 में आत्मदाह की पहली श्रृंखला की शुरुआत हुई। यह शुरुआत भिक्षुओं, भिक्षुओं और पूर्व भिक्षुओं से हुई और यह श्रृंखला करीब एक साल चली। पहले आत्मदाह की तरह ही ऐसी हर घटना स्तब्ध करने वाली होती है। तिब्बती विद्वानों का कहना है कि आत्मदाह करने वाले लोगों के करीबियों से पता चलता है कि ये घटनाएं किसी मठ में किसी दुर्व्यवहार की घटना की प्रतिक्रिया होती हैं। तिब्बती बौद्ध मठों पर अक्सर निगरानी रखी जाती है और उन पर चीनी सुरक्षा बलों का छापा पड़ता रहता है। वर्ष 2012 में इसमें एक बदलाव आना शुरू हुआ। इन घटनाओं पर नजर रखने वाले तिब्बती आंदोलनकारियों और विद्वानों के मुताबिक वर्ष 2012 और 2013 में आत्मदाह करने वाले 100 से ज्यादा लोगों में से करीब दो–तिहाई आम लोग थे।

इनमें से एक रिक्यो नाम की एक महिला पिछले साल मई में जामथांग जोनांग मठ में गई जहां उसने खुद को आग लगा लिया। उसने आत्मदाह के समय जो पत्र लिख छोड़ा है वह स्थिति को बयान करता है। एक बच्चे की मां 33 वर्षीय रिक्यो लिखती हैं कि वह चाहती हैं कि दलाई लामा तिब्बत वापस आएं–आत्मदाह करने वाले लगभग सभी लोगों की यही मांग है। वह अपने पत्र में लिखती हैं, "मैं हर हताश व्यक्ति की पीड़ा सहने को तैयार हूं। यदि मैं कम्युनिस्टों के हाथों पड़ जाती हूं तो कृपया लड़ाई न करना।

बीजिंग ने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया है। उसने कहा कि आत्मदाह करने वाले "आतंकवादी" हैं और उसने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कथित रूप से लोगों को आत्मदाह के लिए उकसाया है। चीनी अधिकारियों ने पिछले साल तिब्बती इलाकों में कम से कम 75 लोगों को गिरफ्तार किया है। बर्मा में एक खंभे पर नोटिस चिपकाया गया है जिसमें उन लोगों को एक लाख युआन (16,310 डॉलर) का ईनाम देने की घोषणा की गई है जो "आत्मदाह की योजना बनाने, समर्थन करने और दूसरों को आत्मदाह के लिए उकसाने या बाध्य करने" वालों के बारे में किसी तरह की जानकारी देंगे।"

चीनी अधिकारियों ने खासकर दलाई लामा पर यह आरोप लगाया है कि वे आत्मदाह करने वाले लोगों के परिवारों को धन दे रहे हैं। चीन सरकार दलाई लामा को "भिक्षु के रूप में भेड़िया" कहती है। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार ने इन

तिब्बत में प्रदर्शन करने वाले तिब्बतियों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने के विरोध में कीर्ति मठ के तिब्बती नवदीक्षित भिक्षुओं ने धर्मशाला, भारत में एक मोमबत्ती जुलूस निकाला। फोटोः एंगस मैकडोनाल्ड/एपी

आरोपों को सिरे से खारिज किया है।

ckjhd j[kk,

आत्मदाह की बढ़ती संख्या दलाई लामा के लिए बेड़ी बन रही है। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को "स्वाभाविक" बताया है, भले ही वह इसे प्रोत्साहित नहीं करते। कई तिब्बती विद्वानों ने उनके रुख की यह कहते हुए आलोचना की है कि अपनी जनता से इसे रोकने के लिए कहने में उनकी हिच. किचाहट ने आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों के संकल्प को और मजबूत किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में आधु. निक तिब्बत अध्ययन के निदेशक रॉबी बार्नेट ने कहा, "इस स्थिति में दलाई लामा द्वारा कोई निर्णायक कदम न उठा पाने और खुद को मार डालने वाले लोगों को अपने ऊपर निर्भर लोगों के बारे में भी सोचने की सलाह देने में विफलता को देखकर मैं हैरान हूं।" इस टिप्पणी के बारे में जब हमने दलाई लामा से प्रतिक्रिया लेनी चाही तो वहां से कोई जवाब नहीं मिला। दलाई लामा के भतीजे खेदरूब थोनडुप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके चाचा एक "विकट परिस्थिति में फंस गए हैं।" उन्होंने कहा कि दलाई लामा के अपील करने से भी आत्मदाह की लहर नहीं रुकने वाली है क्योंकि "यह उनके द्वारा नहीं शुरू किया गया है और वह इसका अंत नहीं कर सकते।" खेदरूब ने कहा, "उनका मानना है कि लोग इस वजह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और वे हताश हैं। जब वे आत्मदाह करते हैं तो वे परमपावन की वापसी की मांग करते हैं।"

निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने एक इंटरव्यू में कहा कि आत्मदाह एक राजनीतिक मसला है। उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया दलाई लामा की तरफ से नहीं बल्कि सांगे की सरकार की तरफ से आनी चाहिए और वह आत्मदाह को हतोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए चीन सरकार जिम्मेदार है और इसका समाधान भी उसी के पास है।

सांगे ने कहा, "उन्हें बस यही करना होगा कि अपनी दमनकारी नीतियों में बदलाव लाएं और तिब्बती जनता के लिए उदार नीतियों की शुरुआत करें और संवाद के माध्यम से तिब्बत मसले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करें।" इस रवैए को तिब्बती "मध्यम मार्ग नीति" कहते हैं जिसके तहत तिब्बती इलाके के लिए हांगकांग जैसी स्वायत्तता की मांग की जा रही है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच वर्षों तक चलने वाली स्वायत्तता की वार्ता वर्ष 2010 में टूट गई। अब आत्मदाह की बढ़ती संख्या ने कुछ तिब्बती आंदोलनकारियों का मध्यम मार्ग नीति के प्रति असंतोष को और बढ़ा दिया है। वे विरोध प्रदर्शन के अहिंसक तरीके का समर्थन करते हुए भी स्वाधीनता चाहते हैं, सिर्फ स्वायत्तता नहीं। मार्च में कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए राष्ट्रपति शी ने तिब्बत के बारे में सार्वजनिक तौर पर बहुत कम बोला है। उनके स्वर्गीय पिता उदार सोच वाले पूर्व उप राष्ट्रपति की दलाई लामा से अच्छी निभती थी। दलाई लामा ने 1950 के दशक में सीनियर शी को एक महंगी घड़ी उपहार में दी थी, जिसे कई दशकों बाद भी वह पहने हुए दिखते थे। जूनियर शी ने इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई है। पिछले साल जुलाई में तिब्बत के एक दौरे के दौरान शी ने अलगाववादियों पर हमला बोलत हुए कहा कि उनका नेतृत्व दलाई लामा कर रहे हैं।

सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने मई के मध्य में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसमें एक गाइडबुक के प्रकाशन के लिए "दलाई गुट" को जिम्मेदार ठहराया गया था। इस गाइडबुक में यह जानकारी दी गई थी कि आत्मदाह कैसे किया जा सकता था। इस आरोप की पुष्टि के लिए निर्वासित तिब्बत सरकार के एक पूर्व सदस्य के उस ब्लॉग पोस्ट का हवाला दिया गया था जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि "सेना जैसी योजना" बनाकर आत्मदाह के असर को ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है, जैसे यदि

कोई व्यक्ति आत्मदाह करता है तो उसका कोई दोस्त उसका फिल्मांकन करे। हालांकि, निर्वासित तिब्बती सरकार ने इस ब्लॉग पोस्ट की आलोचना करते हुए इसे "गैर जिम्मेदार" बताया था।

lenk; dk lEeku

राजनीतिक गतिरोध और दमघोंटू दमन ही वह मानक वजह माने जा सकते हैं जिनकी वजह से आत्मदाह की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ विद्वानों और तिब्बतियों का कहना है कि कालक्यी की मौत में बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। चीन में रहने वाले तिब्बती एक ऐसे चलन को अपना रहे हैं जिसे कुछ विद्वान "सम्मान आधारित राजनीति" कहते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बार्नेट कहते हैं, "बहुत से लोग अपने को सामाजिक रूप से नगण्य समझते हैं, खासकर युवा महिलाएं, इसलिए यह उनके लिए ज्यादा तार्किक लगता है कि पूरे समुदाय के सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दें, जैसा कि समुदाय के अन्य नेता, भिक्षु कर चुके हैं।"

जहां तक आत्मदाह के लहर की बात है–इसमें ज्यादातर आम तिब्बती शामिल हैं–यह 2011 में हुई भिक्षुओं की मौतों को सम्मान देने का एक तरीका है और अपने बलिदान को सार्थक बनाने का। बार्नेट ने कहा कि चिंता की बात यह है कि यह चलन तेजी से आम लोगों में फैल रहा है, जैसे कि कालक्यी जैसी युवा मां जो पहले कभी भी किसी तरह की अवज्ञा करते हुए नहीं पाई गई।

बर्मा कस्बा जिसे चीनी भाषा में झोंगरांगतांग कहते हैं, बहुत ही सुदूर इलाके में करीब और बिखरी जनसंख्या वाला है जिसमें सिर्फ 4,000 लोग रहते हैं। भेड़ की खालों से बने परिधानों से लिपटी औरतें चट्टानों को तोड़ती दिख जाती हैं, ताकि उनसे बजरी बनाई जा सके। इनमें से बहुत कम ही चीनी बोल पाती हैं। एक मुख्य सड़क कस्बे से होकर गुजरती है जो कि समुद्र के स्तर से 3,560 मीटर (11,680 फुट) ऊंचा है और चीड़ के वृक्षों से भरे हुए पहाड़ों से घिरा हुआ है। स्थानीय काउंटी सरकार की वेबसाइट पर वर्ष 2009 में दिए आंकड़ों के अनुसार वहां रहने वाले 96 फीसदी लोग चरवाहे हैं। उनमें से एक कालक्यी के पति ट्रुइप भी हैं। कालक्यी के एक रिश्तेदार ने बताया कि उसके परिवार को उस इलाके का मध्यम वर्गीय परिवार माना जाता था। ट्रुइप ने अपने जानवर बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। उसने एक मकान भी बनाया था। उन्होंने एक मकान बेच दिया था और एक दूसरे मकान में रह रहे थे जो एक दोमंजिला, ईंट–गारे से बनी इमारत थी। एक रिश्तेदार के अनुसार मरने से करीब एक महीने पहले कालक्यी ने बताया था कि वे एक तीसरे मकान का काम पूरा कर चुके हैं जो आधुनिक पत्थर से बनी इमारत थी, लेकिन उसकी साज–सज्जा अभी पूरी नहीं हुई थी। गर्मियों में कालक्यी और ट्रुइपे पहाड़ों पर चढ़कर जड़ी–बूटियां और कवक तोड़ने जाते थे जिसे नीचे लाकर वे बेचते थे। बहुत से तिब्बती नोमैड "इल्ली कवक" की खेती में कुशल होते हैं जो परंपरागत चीनी चिकित्सा में बहुत काम आता है और 2,25,000 युआन (36,700 डॉलर) प्रति किलो बिकता है। इस जोड़े के चार बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 से 10 वर्ष के बीच है। उनके ईंट–गारे से बने मकान के आंगन में एक लंबे खंभे पर लगा तिब्बती धर्म ध्वजा अब हवा में फहर रही है। उनके मकान के सामने की दीवार पर लगे पत्थर में तिब्बती में लिखा हुआ है: "ओम मणि पदमे हम", यह एक परंपरागत बौद्ध मंत्र है जो दलाई लामा के लिए प्रार्थना करते समय भी पढ़ा जाता है।

कालक्यी अशिक्षित थी। चीन सरकार ने 1990 के दशक में ही तिब्बती भाषा के स्कूल बंद कर दिए, इसलिए वह कभी भी लिखना–पढ़ना सीख नहीं पाई और उसने सरकार द्वारा खोले जाने वाले चीनी भाषा के स्कूलों में कभी भी जाना गंवारा नहीं समझा। उसके करीबी बताते हैं कि जब 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई तो वह तिब्बती सीखना चाहती थी ताकि वह प्रार्थना तो कर सके। उसने जामथांग जोनांग जाना शुरू किया जो एक बड़ी इमारत है और जिसके अंदर बड़े प्रांगड़ और छोटी इमारतों के साथ तीन विभिन्न मठ हैं। उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के लोग और दोस्त बताते हैं कि वह एक सुलभ महिला थी, जो अपने गांव के बड़े–बुजुर्गों के साथ बातचीत करना पसंद करती थी। रिश्तेदारों और भारत में रहने वाले तिब्बती सांगयांग ग्यात्सो, जिनका कालक्यी के रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क है, उनके अनुसार कालक्यी का पारिवारिक जीवन स्थिर था और उसे किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं थी।

अपना जान बलिदान करने से पहले के कुछ महीनों और हफ्तों में कालक्यी की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने किसी तरह का राजनीतिक रुझान नहीं दिखाया था। उसके एक करीबी रिश्तेदार ने नाम न छापने की शर्त पर रायटर्स से कहा, "मुझे कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि वह खुद को आग लगा लेगी।" पड़ोसियों के अनुसार उनके पति भी इस घटना से बिल्कुल भौंचक्के रह गए हैं। रायटर्स की ट्रुइप से बात नहीं हो पाई। पुलिस ने रायटर्स के पत्रकारों को उनके घर जाने से रोक दिया और उन्हें छह घंटे तक हिरासत में रखने के बाद कस्बा छोड़कर प्रांत की राजधानी चेंगदू जाने का आदेश दिया। 24 मार्च को कालक्यी की मौत के तत्काल बाद जामथांग जोनाग मठ के भिक्षु उनके शव को मठ के मुख्य हॉल में लेकर गए क्योंकि चीनी सुरक्षा बलों और सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया था। तिब्बती रीति–रिवाजों के मुताबिक शव को संभालकर रखा जाता है और अंतिम संस्कार ज्योतिषी द्वारा तय सबसे पवित्र दिन को ही किया जाता है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चीनी प्रशासन ने आदेश दिया कि कालकी का अंतिम संस्कार आधी रात तक खत्म कर दिया जाए। स्थानीय लोगों के अनुसार इसके बाव. जूद बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी के रहते हुए भी, उस शाम को अंतिम संस्कार स्थल पर करीब 4,000 लोग जमा हुए थे।

करीबी रिश्तेदारों का यह मानना है कि अपने जीवन का बलिदान करने का कालक्यी का निर्णय तिब्बती समुदाय को सम्मान दिलाने के लिए है। एक रिश्तेदार ने कहा, "शायद उसने यह सोचा हो कि वह कभी स्कूल तो जा नहीं सकी, इसलिए इसी तरीके से वह अपने देश के लिए कुछ कर सकती है।" उन्होंने कहा, "उसके आत्मदाह के बाद मैं बहुत दुःखी था, लेकिन इसके बाद मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि एक युवा महिला ने एक बड़े कार्य, राष्ट्रीय कार्य के लिए अपने जीवन को होम कर दिया था।" चीन सरकार को चेताने के लिए वे ऐसा करते रहेंगे।

कालक्यी के आत्मदाह के एक माह के भीतर ही छुगत्सो नाम की एक 20 साल की महिला अपने घर से चढ़ाई कर जामथांग जा. नांग मठ तक पहुंची। 16 अप्रैल को दोपहर करीब 3 बजे उसने खुद को आग लगा लिया और लगभग उसकी जगह उसकी मौत हो गई, जहां कालक्यी ने दम तोड़ा था। छुगत्सो एक तीन साल के बच्चे की मां थी। ◆

चीनी राष्ट्रपति की यात्राः तिब्बत अब भी है मुख्य मसला

अबंती भट्टाचार्य,

(1 जून, 2013)

ली केच्यांग के भारत दौरे ने यह प्रासंगिक सवाल उठाया है कि उनकी यात्रा से भारत के प्रति चीनी सामरिक नीति में कोई बदलाव आएगा या पुरानी नीति ही बरकरार रहेगी। साफतौर से बीजिंग के संदर्भ में देखा जाए तो भारत–चीन के रिश्तों के बीच सबसे मुख्य अड़चन दलाई लामा और तिब्बत का मसला रहा है। यह नए चीनी नेतृत्व के लिए भी मुख्य चिंता का बिंदु है। इसलिए ली की भारत यात्रा को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि इससे भारत–चीन रिश्ते में कोई सुधार होने वाला है, बल्कि इस रूप में इससे इस इलाके में तिब्बत मसले से जुड़ी चीनी चिंता का समाधान होगा।

तिब्बत मसले को हल करने के लिए चीनी नेतृत्व की मौजूदा रणनीति दोतरफा हैः आंतरिक तौर पर यह ऐसी अल्पसंख्यक नीति अपना रहा है जिससे तिब्बतियों को एक चीनी देश के विचार में फंसा लिया जाए और वह आर्थिक रूप से पिछड़े इस इलाके को चीन की मुख्य भूमि से एकीकृत करने के लिए विकास की पश्चिमी रणनीति अपना रहा है। बाह्य स्तर पर इसने भारत और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से निपटने में तिब्बत को प्राथमिक मसला बनाया है क्योंकि इन देशों में चीन की कम्युनिस्ट सरकार के शासन से भागकर आने वाले तिब्बतियों ने बड़ी संख्या में शरण ले रखा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि भारत सरकार चीन के इस मांग को चुपचाप मान लेने को मजबूर हुई है कि भारतीय जमीन पर चीन विरोधी तिब्बती प्रदर्शनों को स्व. ीकार नहीं किया जाएगा और वह अपनी मीडिया को इस बारे में नियंत्रित करेगी कि वे भारत–चीन संबंधों के बारे में "गैर जिम्मेदार तरीके से" भेदभावपूर्ण समाचार न छापें। नेपाल सरकार से तो चीन ने यह भरोसा हासिल कर लिया है कि वह नेपाली जमीन पर किसी भी तरह की चीन विरोधी गतिविधियां नहीं होने देगी। इसके अलावा वर्ष 2010 तक बीजिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार से इस उम्मीद में वार्ता करना जारी रखा कि दलाई लामा को यह सच्चाई स्वीकार करने को मजबूर कर दिया जाएगा कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। राजनयिक और रा. जनीतिक साधनों के अलावा देंग जियोपिंग के सिद्धांतों पर चलने वाले चीनी नेतृत्व ने 1980 के दशक से ही भारत पर यह दबाव बनाए रखा है कि वह सीमा विवाद को परे रखकर (जो कि भारत की मुख्य चिंता है) आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दे। इसकी वजह से भारत–चीन व्यापार में लगातार बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2015 तक इसके 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। अभी तक, चीन की प्राथमिक रणनीति यह रही है कि भारत से रिश्ते के मामले में राजनीति को एक तरफ रखा जाए और पूरी तरह आर्थिक मसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। साफतौर पर उसकी यह रणनीति तो अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन इससे उसको इच्छित परिणाम नहीं मिल पाया है। वर्ष 2008 में तिब्बतियों के विरोध प्रदर्शन और इसके बाद दलाई लामा द्वारा राजनीतिक सत्ता त्यागने के निर्णय से चीनियों को यह संकेत मिल गया कि तिब्बत मसला तो और दुरूह होता जा रहा है। आत्मदाह की 117 घटनाओं ने भी यह साबित किया है कि चीन की आर्थिक विकास की रणनीति खोखली है। भारत के साथ चीन को आ. र्थिक एवं राजनीतिक मसलों को अलग रखने में सफलता जरूर मिली है, लेकिन वह भारत को तिब्बत कार्ड छोड़ने को मजबूर नहीं कर पाया है। चीन ने यह समझ लिया है कि वह भारत सरकार के सहयोग के बिना तिब्बत के मसले को हल नहीं कर सकता जहां दलाई लामा और 1,20,000 तिब्बतियों ने शरण ले रखी है। इस तरह चीन ने साफतौर पर अपने मौज. ूदा आर्थिक संपर्क की रणनीति को इतनी बारीकी से अपना रखा है ताकि तिब्बत में स्थिरता हासिल हो सके। निश्चित रूप से इसका यह भी मतलब है कि राजनीति और अर्थव्यवस्था को अलग रखा जाए और इस तरह भारत से होने वाली बातचीत में तिब्बत या दलाई लामा की कोई चर्चा न हो। अपने पूर्ववर्तियों की तरह नया नेतृत्व भी यही चाह रहा है कि धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार (केंद्रीय तिब्बती प्रशासन) से वार्ता न शुरू की जाए। हालांकि, वह लगातार इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भारत–नेपाल–चीन के बीच एक त्रिपक्षीय सहयोग कायम किया जाए। असल में यूरो जोन के संकट के बाद पश्चिमी दुनिया में चीनी व्यापार सिकुड़ रहा है जिससे यह आर्थिक त्रिकोणीय पुल चीन के लिए अनिवार्य जैसा हो गया है। यूरो जोन के संकट की वजह से तिब्बत की अशांति को दूर करने क लिए उसके पश्चिमी विकास रणनीति को भी धक्का लगा है। संयोग से वर्ष 2012 में नेपाल में चीनी राज. दूत ने कहा था कि चीन "पश्चिम विकास रणनीति" को आगे बढ़ा रहा है और दक्षिण एशिया उसके लिए मुख्य निवेश अवसरों में से है। नेपाल असल में चीन के लिए दक्षिण एशिया तक पहुंच बनाने में बेहद जरूरी स्थल मार्ग प्रदान कर सकता है।"

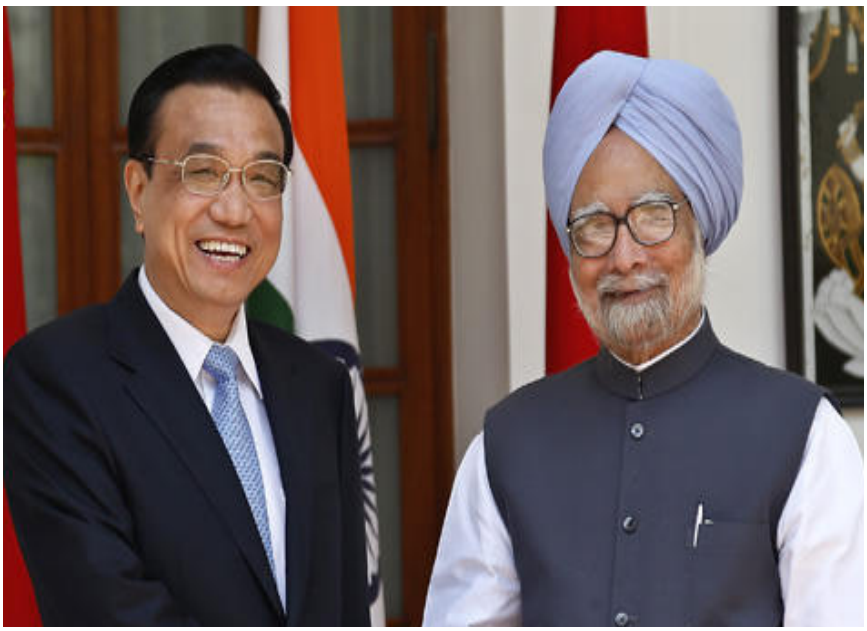

त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने का यह विचार और आगे बढ़ा जब 27 से 30 अप्रैल, 2013 के तक नेपाल के माओवादी नेता पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत दौरे पर आए और उन्होंने त्रिपक्षीय सहयोग का मसला उठाया। इसके कुछ दिनों पहले ही 20 अप्रैल को उन्होंने चीन का अपना दौरा खत्म किया था। साफतौर से चीन लगातार भारत एवं नेपाल के साथ अपने संबंधों और तिब्बत समस्या को एक एकीकृत मसला मानने लगा है और इसलिए वह आर्थिक त्रिपक्षीय एकीकरण के द्वारा इसका क्षेत्रीय समाधान चाह रहा है।

त्रिपक्षीय वाद साफतौर से तिब्बत मसले को हल करने में मदद करेगा, भारत की सहमति से और मुख्यतः भारत, नेपाल और चीन के बीच परस्पर आर्थिक निर्भरता एक मजबूत जाल बुनकर। साफ है कि चीन की यह मृदु रणनीति भारत के तिब्बत कार्ड को हल्का कर देगी। इसके अलावा इससे चीन दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम होगा और उपमहाद्वीप में भारत की श्रेष्ठता कम हो जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दक्षिण एशिया में आर्थिक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में अपने इस योगदान के बदले चीन सार्क की पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने का दावा मजबूत कर लेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली यात्रा के लिए भारत का चयन कर और यह घोषणा कर कि "एक नए तरह का विशाल शक्ति संबंध स्थापित करना है" ली केच्यांग साफतौर पर नई दिल्ली के चीन के विपरीत ध्रुव वाले अमे. रिका से रिश्ते बनाने की इच्छा को दबाना चाहते हैं। चीन इससे भी ज्यादा भारत पर अपनी यह छाप छोड़ना चाहता है कि वह एक महान देश है और पश्चिम से कम नहीं है। लेकिन वह भारत को लुभाने के लिए न तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहा है और न ही अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ रिश्ते कुछ कम करने वाला है, बल्कि वह सिर्फ भारत के साथ एफटीए जैसे अवसर के साथ आर्थिक रिश्ता गहरा करने पर ही जोर दे रहा है। वास्तव में 20 मई 2013 को जिस संयुक्त बयान पर दस्तखत किए गए, उसमें पै. राग्राफ 6 से लेकर 11 तक वित्तीय और आर्थिक संपर्क बनाने पर विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन सीमा जैसे दूसरे मसलों को बाद के पैराग्राफ में निपटाया गया है। सीमा विवाद को 24वें पैराग्राफ में रखा गया है, जबकि यह भारत के लिए एक प्रमुख मसला है। आर्थिक रिश्तों पर अत्यधिक जोर देने के इस खेल से तिब्बत मसले से निपटने में चीनी हित सध ाता है और इससे दक्षिण एशिया में भारत का प्रभाव कम होगा। संयुक्त बयान में पहली बार इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि, "एक उच्च स्तरीय भारत–चीन मीडिया फोरम" का गठन किया जाएगा। अब किसी को यह जिज्ञासा हो सकती है कि भारतीय मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाया जाएगा क्या, क्योंकि चीन सरकार पहले से ही भारतीय मीडिया पर यह आरोप लगाती रही है कि उसकी खबरें भारत–चीन संबंध खराब करने वाली होती हैं। इससे भारत सरकार चीन के हाथों में खेलने लगेगी और अभी भारतीय मीडिया चीनी गतिविधियों पर जो निगरानी रखने का काम करती है, वह विकल्प कमजोर होगा।

इसलिए भारत में ली की यात्रा भारत–चीन रिश्तों में कोई बदलाव लाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ तिब्बत में चीनी चिंता का समाधान करने के लिए और दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए है। इसके लिए चीन असल में भारत से द्विपक्षीय पदों में व्यवहार नहीं करता, बल्कि वह भारत–चीन संबंधों को क्षेत्रीय संदर्भ में ही देखता है। इसलिए वह प्रा. थमिक रूप से इस क्षेत्र के साथ आर्थिक रिश्तों को अपने मुताबिक सही रूप देना चाहता है। इसलिए संयुक्त बयान में ना. थूला सीमा के व्यापार को 16वें पैराग्र. ाफ और बांग्लादेश–चीन–भारत–म्यांमार (बीसीआईएम) उप क्षेत्रीय प्रयासों को 17वें पैराग्राफ में जगह दी गई है।

ली की यात्रा का इरादा कहीं से भी सीमा में घुसपैठ के मसले के लिए किसी हल की पेशकश करना नहीं है। इसलिए अचरज की बात नहीं कि उनके साथ आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में बैंकर, कारा. बारी समूह, वरिष्ठ विकास अधिकारी और बुनियादी ढांचे से जुड़े एक्जिक्यूटिव थे। साथ ही, ली अब व्यापारिक असंतुलन की भारत की चिंता पर भी ध्यान दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आ. र्थिक क्षेत्र में भारत–चीन संबंध अब भी मजबूत नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि ली चीन के राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने आए थे, न कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने।

(अबंती भट्टाचार्य दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्वी एषियाई अध्ययन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह डीफेंस स्टडीज़ और एनालिसिस इंस्टीट्यूट में एसोसिएट फेलो थीं।) ◆

चीन का छद्म युद्ध

¼izkstsDV flafMdsV] 10 twu] 2013½

Czgek psykuh

चीन दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में यथास्थि. ति को बिगाड़ रहा है और वह अंतरराष्ट्रीय नदी धाराओं के लिए भी चिंता पैदा कर रहा है–यह सब वह एक गोली चलाए बिना करने में सफल है। जैसे कि उसने 1950 के दशक में चोरी–छिपे घुसपैठ कर समूचे हिमालयी क्षेत्र में जमीनें हड़प ली थीं, उसी तरह अब चीन अपने एशियाई पड़ोसियों के प्रति छद्म युद्ध चला रहा है जिससे समूचे इलाके में अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। चीन जितना ही आर्थिक ताकत हासिल कर रहा है, क्षेत्रीय यथास्थिति में बदलाव की उसकी आकांक्षा उतनी ही बढ़ती जा रही है।

एक गरीब देश से संपन्न देश बनने और अब वैश्विक आर्थिक ताकत बनने के पूरे इतिहास में उसकी शासन कला और सामरिक रणनीति काफी हद तक एक जैसी रही है। माओत्से तुंग के युग से ही चीन झू वंश के सैन्य रणनीतिकार सुन जू के इस परामर्श को मानता रहा हैः "शत्रु को बिना किसी युद्ध के अपने अधीन करो, ऐसा उसकी कमजोरियों का दोहन करके और आक्रमण को बचाव का छद्म रूप देकर किया जा सकता है।" सुन की यह बात काफी मशहूर है कि, "सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं।" चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर देंग जियोपिंग की पकड़ होने के दो दशकों से भी ज्यादा समय बाद, चीन ने अपने अन्य एशियाई पड़ोसी देशों के साथ "अच्छे पड़ोसी" का रिश्ता बनाए रखा, जिससे उस दौरान वह आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर सका। जैसे–जैसे चीन का आर्थिक एवं सामरिक आभामंडल बढ़ता गया उसके पड़ोसियों को उसके तेज जीडीपी बढ़त का फायदा मिला, और इससे वे भी अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति दे पाए। लेकिन पिछले दशक में किसी मोड़ पर चीनी नेताओं ने साफतौर पर यह निर्णय ले लिया कि आखिरकार उनके देश का वक्त आ चुका है, जिसके बाद उसका "शांतिपूर्ण उभार" ज्यादा हठधर्मी रवैए के लिए रास्ता तैयार करने लगा।

चीन के उभार के बाद ऐसे पहले बदलाव का लक्षण तब देखा गया जब चीन ने 2006 में अपने लंबे समय से दबी पड़ी इस मांग को फिर से दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अपने "मुख्य हितों" को व्यापक रूप देने के लिए चीन ने जल्दी ही अपने कई पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद करने शुरू कर दिए। पिछले साल, चीन ने समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौते का हवाला देते हुए औपचारिक तौर पर दक्षिण चीन सागर के 80 फीसदी से ज्यादा हिस्से पर अपना दावा किया। अपनी मजबूत व्यापारिक स्थिति और महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिज संसाधनों के वैश्विक उत्पादन पर अपने करीब एकाधिकार जैसी स्थिति का फायदा उठाते हुए चीन ने एशिया में एक ज्यादा प्रभुत्वकारी भूमिका हासिल की है। वास्तव में चीन ने जितने ही खुले तरीके से बाजार पूंजीवाद को अपनाया है, वह उतना ही ज्यादा राष्ट्रवादी हुआ है। उसके नेताओं ने इस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है क्योंकि उन्हें राजनीतिक वैधता के एक स्रोत के रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत का कोई विकल्प चाहिए था। इस प्रकार क्षेत्रीय आक्रामकता एक राष्ट्रीय पुनरुत्थान में गुंथी हुई थी।

चीन का संसाधन आधारित छद्म युद्ध एशिया में भू–राजनीतिक स्थिरता का एक बड़ा कारण बन रहा है। चीन जिस तरह के साधनों का इस्तेमाल करता है वह विविधतापूर्ण होते हैं और उनमें अर्द्धसैन्य समुद्री एजेंसियों के आवरण में छुपे योद्ध ाओं का एक नया वर्ग शामिल होता है। और उसको इससे कुछ जीत भी हासिल हो चुकी है।

पिछले साल, चीन ने दक्षिण चीन सागर के एक इलाके स्कारबोरो शोआल पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया, जब कि इस इलाके पर फिलीपींस और ताइवान भी अपना दावा कर रहे थे। इसके लिए उसने इलाके में अपने जहाज भेजे और कुछ एंट्री बैरियर लगाकर फिलीपींस के मछुआरों को उस इलाके में प्रवेश करने से रोक दिया। तबसे चीन और फिलीपींस के बीच इसे लेकर गतिरोध बना हुआ है। अब फिलीपींस के सामने हाबसन का यह साम. रिक विकल्प ही बचा है कि वहः चीन द्वारा निर्देशित इस सच्चाई को स्वीकार करे या एक खुले युद्ध का जोखिम झेलने को तैयार रहे। चीन ने पूर्वी चीन सागर में एक छद्म युद्ध भी शुरू किया है ताकि संसाधन बहुल सेनकाकु द्वीप (जिसे चीन में दियाओयु द्व ीप कहा जाता है) पर अपना क्षेत्रीय दावा मजबूत किया जा सके, जबकि 1895 से ही इस पर जापान का कब्जा है (1945 से 1972 के बीच अमेरिका द्वारा प्रशासित कुछ वर्षों को छोड़कर)। चीन का यह खुला दांव सफल हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस इलाके को विवादित मानने को मजबूर कर दिया जाए और उसने यथास्थिति को बिगाड़ने का आभास करा दिया है।

इसी तरह चीन भारत के सामने भी नई चुनौतियां पेश कर रहा है, वह उसे एक ही दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए कई मोर्चों पर दबाव बना रहा है, जिनमें पुराने क्षेत्रीय दावे को नए सिरे से उभारने जैसे मोर्चे भी हैं। यह देखते हुए कि दोनों देश दुनिया की सबसे लंबी विवादित सीमा साझा करते हैं, भारत पर चीन के सीधे सैन्य दबाव का पड़ने का जोखिम सबसे ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश (जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कहता है) के जिस विशाल भू–भाग पर चीन अपना दावा करता है, वह आकार में ताइवान से करीब तीन गुना बड़ा है। हाल

ब्रह्मा चेलानी

के वर्षों में चीन ने लगातार हिमालयी सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास किया है और संसाधन बहुल अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू–कश्मीर के लद्दाख इलाके में वह कई बार इसमें सफल भी रहा है क्योंकि सीमाव. र्ती इलाका विशाल, रहने योग्य नहीं है और उसकी निगरानी करना कठिन है। चीन का उद्देश्य यह है कि भारत को चिकोटी काटते रहें और जितना संभव हो उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से नीचे की ओर ध ाकियाते रहें। वास्तव में 15 अप्रैल को चीनी सेना की एक पलटन ने लद्दाख इलाके में रात के समय चुपचाप नियंत्रण रेखा को पार कर लिया और भारतीय सीमा के 19 किमी. तक अंदर घुसकर अपना शिविर बना लिया। इसके बाद चीन ने प्रतिरोधी राजनय का सहारा लेते हुए अपनी सेनाओं को तभी वापस लिया, जब भारत ने अपनी सीमावर्ती इलाके में कुछ निर्माण कार्य को नष्ट किया। उसने भारत को समझौते का एक एकतरफा प्रारूप भी सौंपा है जिसमें यह मांग की गई है कि भारत सीमा पर अपनी रक्षा के लिए जो भी देर से और अनाड़ीपन में निर्माण कर रहा है, उसे भी रोका जाए, जिससे बिना चेतावनी के चीन के हमले की क्षमता और पुख्ता हो जाएगी।

भारत ने अपनी तरफ से समझौते का एक प्रारूप पेश किया जो खासकर सीमा पर झड़प को रोकने के लिए बनाई गई थी। लेकिन चीनी छद्म युद्ध का उद्देश्य सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं है, वह नदियों के तटों पर स्थित देशों के साथ भी रिश्तों के मामले में यथास्थिति को बिगाड़ना चा. हता है। वास्तव में उसने चोरी–चोरी सीमा. पार तक बहने वाली नदी जलधाराओं को मोड़ने के लिए बांध परियोजनाएं शुरू की हैं और अपने पड़ोसी देशों की परिस्थितियों का फायदा उठाया है। एशियाई देशों को (अमेरिका के साथ मिलकर) एशिया की सुरक्षा में खामी को दूर करना चाहिए और क्षेत्रीय शर्तें तय करनी चाहिए। लेकिन चीन का शासन करने का तरीका, जिसमें वह सहयोग के कार्ड के बहाने प्रभुत्व और छल–कपट का सहारा लेता है, इस तरह के प्रयासों में रोड़ा डाल रहा है। इससे इस इलाके में भूमिका निभाने वाला एक और बड़ा अदाकार अमेरिका दुविधा में पड़ गया है: चीन द्वारा लगातार यथास्थिति को बिगाड़ने और अमेरिका के सहयोगियों एवं सामरिक साझेदारों को कमजोर करने का खेल देखते रहें या एशियाई देश चीन के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ते हुए इस पर कुछ प्रतिक्रिया करें, जबकि चीन उसके हितों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण एशियाई देश है। इन दोनों में से किसी भी एक विकल्प के बहुत दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने का एक ही रास्ता बचता है कि एक तीसरे विकल्प पर आगे बढ़ा जाए: चीन को इस बात के लिए प्रे. रित करना कि वह यथास्थिति को स्वीकार करे। इसके लिए एक नए तरह के शासन पद्धति की जरूरत होगी जो परस्पर फायदे के सहयोग पर आधारित हो, ब्रिंकमैनशिप या कपट पर नहीं।

(लेखक नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सामरिक अध्ययन के प्रोफेसर हैं और उन्होंने 'एशियन जगरनॉट, वाटर: एशियाज न्यू बैटलग्राउंड' और 'वाटर, पीस ऐंड वार: कनफ्रंटिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस' जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं) ◆

तिब्बतियों को अभूतपूर्व तरीके से साबित करनी पड़ रही है अपनी वफादारी

तिब्बत की राजधानी ल्हासा के बारखोर में स्थित जोखांग मंदिर की परिक्रमा कर रहे बौद्ध तीर्थयात्रियों पर नजर रखे हुए सुरक्षा गार्ड।
फोटोः ग्रेग बाकेर, फाइल/एपी

¼frCcru jh0;| MkV uV] 20 tu] 2013½

संभावित बागियों को अलग–थलग करने और उनके पीछे पड़ जाने, तथा उनकी धार्मिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रत को सीमित करने के लिए चीन ने करीब 21,000 अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी कैडर को समूचे तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) के गांवों तक भेजा है। दिखाने के लिए तो इनका काम पार्टी का आधार बढ़ाना है, लेकिन ये लोग अनुचित तरीके से लोगों की निगरानी कर रहे हैं, व्यापक राजनीतिक पुनर्शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं और पार्टी की सुरक्षा ईकाई का गठन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क आधारित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वाच ने 19 जून को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। ग्रुप का कहना है कि यह अभियान ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार के बह. ाने चलाया जा रहा है। संगठन ने कहा, "पार्टी द्वारा टीएआर में 10 अक्टूबर, 2011 को पार्टी नेतृत्व के द्वारा शुरू किया गया यह अभियान तीन साल की अवधि का करीब आधा समय पूरा कर चुका है। इसके तहत 5,000 से ज्यादा अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को "बुनियाद को मजबूत करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ" के सरकारी अभियान के तहत तिब्बती गां. वों में भेजा गया है।" संगठन ने बताया कि उसके अध्ययन से यह पता चला कि गांव–गांव में पहुंचे सरकारी दल के ये लोग तिब्बतियों को उनकी धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं और उनके व्यवहार एवं विचारों पर निगरानी रखने के लिए संस्थाएं खड़ी कर रहे हैं।

संगठन ने कहा कि यह अभियान

वर्ष 2011 में टीएआर में शुरू किए गए तीन बड़े सामाजिक संगठन और नियंत्रण प्रणालियों में से एक है। अन्य व्यवस्थाओं में एक शहरी प्रशासनिक ने. टवर्क भी है जिसमें टीएआर में वर्ष 2012 में शुरू किए गए ग्रिड सिस्टम कहलाने वाली काफी बढ़ा दी गई निगरानी एवं चौकसी व्यवस्था और तिब्बत के मठों में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के बारे में सूचनाएं जुटाने की एक नई व्यवस्था जिसे "सिक्स वन्स" कहा जाता है। इन तीन निगरानी एवं चौकसी व्यवस्थाओं को आधिकारिक तौर पर "स्थिरता बनाए रखने" के उपायों को बढ़ावा देने वाला बताया जाता है। मार्च 2013 में टीएआर के पार्टी सचिव छेन गुओकियांग ने इस अभियान को टीएआर में "सबसे बड़ी प्राथमिकता" बताया है। "लोगों को फायदा पहुंचाओ" के इस अभियान का लक्ष्य "तीन संयोग" को हासिल करना है, जिसका निहितार्थ है किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या असंतोष न होने देना है। बताया जाता है कि इन टीमों को यह निर्देश दिया गया है कि वे पहली प्राथमिकता तिब्बती गांवों में पार्टी की भूमिका आधार बढ़ाए। दूसरी प्राथमिकता "दलाई गुट के खिलाफ गतिविधियां चलाकर स्थिरता कायम रखना" है। संगठन का कहना है कि इन उपायों को लागू करने से लोगों की धार्मिक आज़ादी और धर्म के पालन पर अंकुश लगाया जा रहा है। यह अभियान टीएआर के बाहर कुछ तिब्बती इलाकों में भी हो रहा है।

इस सवाल पर कि ये टीमें अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर रही हैं, संगठन ने एक ग्रामीण का हवाला दिया जिसके अनुसार ल्हासा प्रशासनिक क्षेत्र के ता. कत्से काउंटी में पार्टी कैडर टीम ने गांव में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ किया, यहां तक कि छोटे बच्चों से भी पूछताछ की गई और इसके बाद उन्हें तीन वर्गों में बांट दिया गयाः पहला, ऐसे लोग जो धन चाहते हैं और मौज. ूदा व्यवस्था का समर्थन करते हैं, दूसरे ऐसे लोग जो गुप्त तरीके से तो दलाई लामा की प्रार्थना करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, लेकिन खुलकर विरोध प्रदर्शन नहीं करते, तीसरा ऐसे लोग जो "पुनर्शिक्षा को स्वीकार नहीं करते और मातृभूमि एवं पार्टी में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते।" इस वर्गीकरण से यह पता चला कि तीसरे वर्ग में 135 लोग हैं और मार्च महीने में उन्हें "काउंटी केंद्र में ले जाया गया और 45 दिन तक पुनर्शिक्षा के लिए रखा गया।"

इन लोगों ने यह भी बताया कि नागछू के 500 ग्रामीणों को इस दा. ौरान पुनर्शिक्षा के लिए हिरासत में ले लिया गया। एक और व्यक्ति ने बताया कि ल्हासा के मेलड्रो गुंगकार काउंटी के भी 73 लोगों को पुनर्शिक्षा के लिए भेजा गया था। संगठन ने एक आधि ाकारिक रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें चामदो प्रशासनिक क्षेत्र के एक गांव में एक कैडर टीम के कामकाज के बारे में गांव वालों ने बताया कि इस टीम ने रह गांव वाले के सामाजिक संपर्क के बारे में पूछताछ की। इन दलों ने गांव के "प्रमुख लोगों" के बारे में जानकारी इकट्ठा की और उनके "ऊपर गहरी नजर बनाए हुए हैं।" ये प्रमुख लोग आमतौर पर उनको मानते हैं जो राजनी. तिक अशांति पैदा कर सकते हैं। इस अभियान के तहत हर कैडर टीम को अलगावादियो के खिलाफ संघर्ष में हर गांव को "एक किले" में तब्दील करना पड़ता है और इसके लिए एक नई पार्टी कमेटी के गठन के साथ ही ऐसे लोगों को भी मनाना होता है जो "धनी बनने और पार्टी का सदस्य और गांव का नेता बनने को तैयार हैं।"

इस अभियान का दूसरा उद्देश्य यह है कि तीन तत्वों पर आधारित हैः "सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना", दलाई लामा के अनुयायियों के खिलाफ "संघर्ष को तेज करना" और "बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के प्रबंधन एवं शिक्षा को मजबूत करना" है। इसके तहत कैडर टीमों द्वारा ग्रामीण परिवारों के बीच दलाई लामा के समर्थन के बारे में सूचनाएं जुटाने का कार्य तेज करने, सुरक्षा अभियान का चलाना और दलाई लामा के समर्थन को खत्म करने के लिए निगरानी प्रणाली का गठन करना है। रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी, 2013 को टीएआर में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी हाओ पेंग (उप क्षेत्रीय पार्टी सचिव और उप क्षेत्रीय सरकारी चेयरमैन जिन्हें हाल में ही मार्च में उनके ट्रांसफर के बाद क्विंघई प्रांत का गवर्नर बनाया गया है) ने अर्द्धसैनिक दलों को बताया कि उन्हें "अच्छी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी तरह का भी साया, कोई खामी, कोई दरार न हो और देश विरोधी ता. कतों को जरा भी मौका न मिले। उन्हें निगरानी और खुफिया सूचनाएं जुटाने का काम पुख्ता करना चाहिए।"

संगठन ने कहा कि यह अभियान अपने आकार, संभावना और लागत के लिहाज से अभूतपूर्व है। आधिका. रिक रिपोर्ट के अनुसार चीन गणराज्य की स्थापना के बाद पहली बार करीब 21,000 कार्यकताओं–प्रांतीय स्तर के कैडर का सबसे बड़ा हिस्सा–को देहाती क्षेत्रों में भेजा गया है। वे तीन साल के अभियान के तहत टीएआर के 5,451 गां. वों में चार या इससे अधिक के समूह में रह रहे हैं। इस अभियान पर एक साल में 1.48 अरब युआन (करीब 22.7 करोड़ डॉलर) की लागत आएगी और क्षेत्रीय सरकार के बजट का 25 फीसदी से ज्यादा हिस्से के अलावा 10 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि गांवों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटित की गई है।

इस टीम के काम का एक छोटा हिस्सा यह भी है कि वे "कठिनाइयों का समाधान करें और आर्थिक विकास को बढ़ावा दें" जैसे बर्फ को हटाने, पानी तक पहुंच, सड़क निर्माण, सौर ऊर्जा की आपूर्ति, साक्षरता की कक्षा और मनोरंजन या संचार के साधनों को खरीदने में गांव वालों की मदद और उनकी कुछ व्यावहारिक और आर्थिक दिक्कतों को भी दूर करना। हर टीम को हर गांव में खर्च के लिए सालाना एक लाख युआन (16,000 डॉलर) का बजट दिया गया है।◆

द ओपन रोड

चौदहवें दलाई लामा की वैश्विक यात्रा

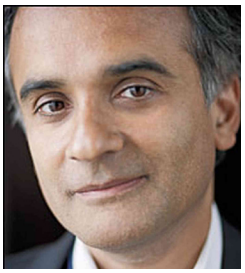

fidk v;;j

14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो की विस्तृत छवि पेश करने वाली यह किताब ऐसे समय में किताबों की दुकानों में पहुंची है, जब तिब्बती ल्ह.ासा की सड़कों और 'बर्फ की भूमि' के अन्य जगहों पर मार्च कर रहे हैं। अय्यर ओपन रोड की शुरुआत दो युवा व्यक्तियों की मुलाकात से करते हैं "जिनमें कई चीजें आम हैं...दोनों यात्रा पसंद करने वाले हैं, निर्वासित हैं...दोनों दार्शनिक हैं...दोनों ऐसे जमाने के हैं, जब संस्कृतियां एक–दूसरे के इतने करीब पहुंच सकती हैं, जितना पहले कभी नहीं हुआ था।" ये दो व्यक्ति हैं दलाई लामा और पिको के पिता। कुछ वर्षों के बाद सीनियर अय्यर ने एक किताब लिखी जिसके लिए दलाई लामा ने भूमिका लिखी थी। यह पुस्तक पिको और उन "पीढ़ियों के लोगों को समर्पित थी जिनके लिए कोई पर्दा नहीं था।"

कई दशक बाद पिको को इस छोटे से वाक्य का गहरा अर्थ समझ में आया और उन्होंने अपने पिता के साथ युवा दलाई लामा की मुलाकात को याद किया है। "शांतिपूर्ण क्रांति के वशीभूत हो वह मुनादी करते हैं, हमें चुनौती देते हैं कि राजनीति, वैश्वीकरण, सेलेब्रिटी को बड़े और ज्यादा रोशनी में देखें।" इस पुस्तक को यह बात खास बनाती है कि अय्यर तिब्बती नेता के साथ अपनी कई मुलाकातों, उनके दर्शन और इंटरव्यू से एक ऐसे व्यक्ति के समृद्ध व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने में सफल रहे हैं जो पूर्वोत्तर तिब्बत के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में पैदा हुआ और जिसकी तकदीर में इस ग्रह के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की कतार में शामिल होना लिखा था। जब कोई दलाई लामा से मिलता है तो उन्हें सबसे ज्यादा जो बात प्रभावित करती है, वह है उनका किसी तरह के दिखावे से दूर रहना, वह अक्सर यह दोहराते हैं, "मैं सिर्फ एक सामान्य बौद्ध भिक्षु हैं।"

अय्यर को इस भिक्षु की कहानी और दुनिया से उनके निपटने का तरीका मंत्रमुग्ध करता है। सबसे पहले उन्हें इस बात पर काम करना होता है जिसे अय्यर 'परी कथा' कहते हैं: "उनकी तलाश पूरी हुई...जब ल्हासा के पूर्वोत्तर आकाश में एक इंद्रधुनष बनता दिखाई दिया, पोटाला महल के एक खंभे पर तारे जैसी आकृति दिखाई दी और 13वें दलाई लामा का सिर बार–बार पूर्वोत्तर दिशा में घूम जाने लगा।" क्या तिब्बत अब भी करोड़ों

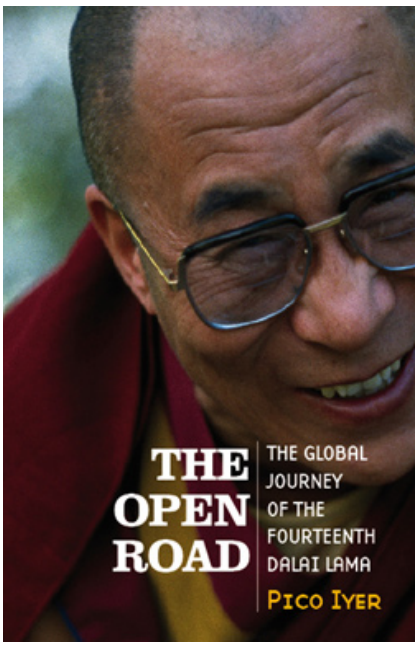

लोगों के लिए मिथक जैसा नहीं है? हालांकि, अय्यर उन लोगों की आलोचना करते हैं जो उन्हें "किसी अन्य ऐसी दुनिया के दूत के रूप में देखते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है।"

दलाई लामा सबसे पहले और मुख्यतः एक बौद्ध भिक्षु हैं, इसलिए वह ज्यादा यथार्थवादी हैं। करीब 2,500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जिसे तिब्बती नेता "अपना स्वामी" कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था: "जैसा बुद्धिमान लोग सोने की परख उसको जलाकर, काटकर और उसे एक कसौटी पर रगड़कर करते हैं, उसी तरह आपको मेरे शब्दों को परखने के बाद ही स्वीकार्य करना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरा सम्मान करते हैं।"

दलाई लामा इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि यदि "आधुनिक विज्ञान" यह साबित करता है कि धर्मग्रंथ गलत हैं तो आपको "वैज्ञानिक तथ्यों" पर ही भरोसा करना चाहिए, न कि उन बातों पर जो 2000 साल पहले लिखी गई हों। यदि सभी धार्मिक नेता आज ऐसे ही बुनियादी सत्य बोलने लगें तो दुनिया के 90 फीसदी से ज्यादा टकराव अपने आप खत्म हो जाएंगे।

इस "साधारण भिक्षु" की एक और विलक्षणता यह है कि वह अक्सर यह कहने की हिम्मत करते हैं कि "मैं नहीं जानता"। यह किसी धार्मिक (या राजनीतिक भी) अगुआ के लिए असामान्य बात ही है। इसके अलावा, वाद–विवाद के माहौल के बीच प्रशिक्षित एक भिक्षु की तरह दलाई लामा ने बचपन से ही यह सीखा है कि किस तरह परस्पर विरोधी विचारों का परीक्षण करें और उनका सामना करें।

चीन के साथ उनकी 'मध्यम मार्ग' नीति पर चलने वाली वार्ता असल में दूसरे पक्ष को समझने की उनकी लगातार इच्छा का ही परिणाम है। वर्ष 1998 में उन्होंने तय किया कि वह चीन से अलग नहीं होंगे बल्कि उसके साथ एक संघ बनाएंगे। हालांकि, युवा तिब्बतियों का एक वर्ग इस रुख की सराहना नहीं करता, लेकिन उनका मानना है कि लांग टर्म में इससे तिब्बत और चीन दोनों को बहुत फायदा होगा।

कुछ साल पहले मैंने बीजिंग के साथ वार्ता में दलाई लामा के विशेष दूत लोदी ग्यारी का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था, "यदि परमपावन दलाई लामा के नतीजों का कुछ फल मिलता है, तो इससे चीन में बुनियादी बदलाव आ सकता है।"

कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट थर्मन ने अपनी किताब 'व्हाय द दलाई लामा मैटर्स' में तर्क देते हैं कि चीनी नेता "संभवतः इस ग्रह के सबसे प्रशंसित व्यक्ति पर कीचड़ उछालकर खुद को ही कलंकित करते हैं", लेकिन जल्दी ही वे समझ जाएंगे कि "दलाई लामा अपने आप में एक समाधान हैं। दलाई के पास सबसे के फायदे के लिए कुछ है। वह ऐसे बोद्धिसत्व हैं जिनसे सबको फायदा होता है।" अय्यर और थर्मन की तरह बहुत से अन्य लोगों का यह मानना है कि दलाई लामा चीन को सोवियत संघ की तरह बिखरने से बचा सकते हैं। ◆